वाई. ए. अजित

बनाम

सोफ़ाना अजित

सितम्बर 7, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 24-स्थानांतरण याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत-अपील पर, माना गया; उच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा।

शब्द और वाक्यांश; अभिव्यक्ति ''कार्रवाई का कारण'' का अर्थ

वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के तहत दायर स्थानांतरण याचिका को अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1. सिविल मामलों में, आम तौर पर अभिव्यक्ति ''कार्रवाई का कारण'' उपयोग किया जाता है जबकि आपराधिक मामलों में जैसा कि धारा 177 सीआरपीसी में कहा गया है, संदर्भ स्थानीय क्षेत्राधिकार का है जहां

अपराध किया गया है। व्युत्पत्ति संबंधी अभिव्यक्ति में ये भिन्नताएँ वास्तव में स्थिति को भिन्न नहीं बनाती हैं। (पैरा 4) (811-ए)

1.2. अभिव्यक्ति ''कार्रवाई का कारण'' ने न्यायिक रूप से तय अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में कार्यवाही के कारण का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो कार्यवाही के अधिकार या तात्कालिक अवसर का उल्लंघन करती हैं। व्यापक अर्थ में, इसका मतलब कार्यवाही के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें हैं जिसमें न केवल कथित उल्लंघन, बल्कि अधिकार के साथ जुड़ा उल्लंघन भी शामिल है। अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति का मतलब हर उस तथ्य से है, जिसे अदालत के फैसले के प्रति अपने अधिकार या शिकायत का समर्थन करने के लिए शिकायतकर्ता के लिए साबित करना आवश्यक होगा। प्रत्येक तथ्य, जिसे साबित करना आवश्यक है, साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े से अलग, जो ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, ''कार्रवाई का कारण'' में शामिल है। अभिव्यक्ति ''कार्रवाई का कारण'' को आम तौर पर ऐसी स्थिति या तथ्यों की स्थिति के रूप में समझा जाता है जो किसी पक्ष को अदालत या न्यायाधिकरण में कार्रवाई बनाए रखने का अधिकार देता है; प्रवर्त्तनशील तथ्यों का एक समूह जो एक या अधिक आधारों को जन्म देता है; एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अदालत में उपचार प्राप्त करने का

अधिकार देती है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट के लिए मामले पर पुनर्विचार करना उचित है (पैरा 4 और 7) (811 डी-जी; 812-ई)

वाई. अब्राहम अजित और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य.. (2004) 8 एससीसी 100, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील संख्या 4110

मद्रास उच्च न्यायालय के स्थानांतरण सी.एम.पी. क्रमांक 12279/2004 में निर्णय और आदेश दिनांक 16.06.2004 से।

टी. एल. विश्वनाथ अय्यर, क्रिष्णन नंदकुमार और टी.जी. नारायणन; अपीलकर्ता के लिए।

वी.एन. रघुपति; प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमोदनस्वीकृत।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में सीपीसी) की धारा 24 के संदर्भ में प्रतिवादी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका स्वीकार की गई है। स्थानांतरण याचिका के माध्यम से प्रतिवादी ने नागर कोइल में जिला न्यायाधीश,

कन्याकुमारी के न्यायालय में लंबित 2003 के आईडी ओपी नंबर 46 को पारिवारिक न्यायाधीश, चेन्नई के न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने प्रार्थना स्वीकार कर ली।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के बीच पहले की कार्यवाही वाई अब्राहम एथ और अन्य बनाम वी. पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य (2004(8) एससीसी100) में इस न्यायालय के समक्ष आई थी व यह कथन किया कि उक्त मामले में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

4. वाई. अब्राहम अजित के मामले (सुप्रा) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया:

जैसा कि ब्लैक स्टोन ने कहा, ‘‘सभी अपराध स्थानीय होते हैं परन्तु अपराध पर अधिकार क्षेत्र उस देश का होता है जहां अपराध किया गया है।" दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में ‘संहिता’) की धारा177 में प्रयुक्त एक महत्वूपर्ण शब्द ‘‘सामान्यतः’’ है।शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि प्रावधान सामान्य है और इसे संहिता में निहित विशेष प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि न्यायालय ने पुरूषोत्तमदास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (एआईआर 1961 एससी 1589), एल. एन. मुखर्जी

बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1961 एससी 1601), बनवारी लाल झुनझुनवाला और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (एआईआर 1963 एससी 1620), मोहन बैठा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2001 (4) एससीसी 350) के मामले में देखा। शब्द "सामान्यतः" द्वारा निहित अपवाद को विशेष रूप से कानून द्वारा प्रदान किए गए अपवादों तक सीमित नहीं होना चाहिए और अपवाद कानून द्वारा विचार पर प्रदान किए जा सकते हैं या उसी न्यायालय द्वारा अपराधों का संयुक्त विचारण की अनुमति देने वाले कानून के प्रावधानों से निहित हो सकते हैं। ऐसा कोई अपवाद मौजूदा मामले पर लागू नहीं है।

जैसा कि इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी और अन्य (एआईआर 1973 एससी 908) में देखा था, निरंतर अपराध वह अपराध है जो निरंतरता के प्रति संवेदनशील एवं एक बार और हमेशा के लिए किए जाने वाले अपराध से पृथक होता है। यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम अथवा आवश्यकता की अवज्ञा या अपालना की विफलता से उत्पन्न होता है और इसमें दण्ड, दायित्व पालना होने तक जारी रहता है, प्रत्येक अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा अथवा अपालना कारित अथवा पुनर्कारित होती है, वहां अपराध हो जाता है। अपराध को जारी रखने से संबंधित एक समान याचिका की जांच इस न्यायालय द्वारा श्रीमती सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी (1997 (5) एससीसी 30) में

की गई थी। वहां आईपीसी की धारा 498ए, 506 और 323 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के संबंध में आरोप थे। तथ्यात्मक पृष्ठभुमि पर, यह नोट किया गया कि यद्यपि दहेज की मांग पहले की गई थी, शिकायतकर्ता का पति उस स्थान पर गया जहां शिकायतकर्ता रहती थी और उसके साथ मारपीट की थी। इस न्यायालय ने उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में माना कि धारा 178 का खंड(सी) आकर्षित होता है।लेकिन वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति अलग है और शिकायतकर्ता ने पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा कथित दहेज की मांग के कारण 15.4.1997 को पति का घर छोड़ दिया।इसके बाद चेन्नई में दहेज की मांग या किसी भी अपराध को अंजाम देने के आरोप की भनक तक नहीं लगी। ऐसा होने पर, अपराधों को जारी रखने से संबंधित संहिता की धारा 178 (सी) का तर्क लागू नहीं किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कार्रवाई का कारण का कोई भी हिस्सा संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। संहिता की धारा 177 के अनुसार यह वह स्थान है जहां अपराध किया गया था।संक्षेप में यह आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का कारण है।

जबकि दीवानी मामलों में, आमतौर पर अभिव्यक्ति ‘‘कार्रवाई का कारण’’ का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपराधिक मामलों में संहिता की धारा 177 में कहा गया है, स्थानीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में जहां अपराध

किया गया है। अभिव्यक्ति में ये व्युत्पत्ति संबंधी भिन्नताएँ वास्तव में स्थिति को भिन्न नहीं बनाती हैं। इसलिए अभिव्यक्ति ‘‘कार्यवाही का कारण’’ आपराधिक मामलों से अछूता नहीं है।

यह स्थापित कानून है कि ‘‘कार्रवाई का कारण’’ में तथ्यों का समूह शामिल होता है, जो अदालत में निवारण के लिए कानूनी जांच को लागू करने का कारण देता है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है, जो उन पर लागू कानून के साथ मिलकर कथित रूप से प्रभावित पक्ष को प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ राहत का दावा करने का अधिकार देता है। इसमें पश्चात्वर्ती कोई कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्य के अभाव में कार्यवाही का कोई कारण संभवतः प्रोद्भूत नहीं होगा या उत्पन्न नहीं होगा।

अभिव्यक्ति ‘‘कार्रवाई का कारण’’ ने न्यायिक रूप से तय अर्थ प्राप्त कर लिया है।प्रतिबंधित अर्थ में कार्यवाही के कारण का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो कार्यवाही के अधिकारया तात्कालिक अवसर का उल्लंघन करती हैं। व्यापक अर्थ में, इसका मतलब कार्यवाही के रख रखाव के लिए आवश्यक शर्तें हैं जिसमें न केवल कथित उल्लंघन, बल्कि अधिकार के साथ जुड़ा उल्लंघन भी शामिल है।अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति का मतलब हर उस तथ्य से है, जिसे अदालत के फैसले के प्रति अपने अधिकार या शिकायत का समर्थन करने के लिए शिकायतकर्ता के लिए साबित करना आवश्यक होगा। प्रत्येक तथ्य, जिसे साबित करना आवश्यक

है, साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े से अलग, जो ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, ''कार्रवाई का कारण'' में शामिल है।

अभिव्यक्ति ''कार्रवाई का कारण'' का उपयोग कभी-कभी उन तथ्यों या परिस्थितियों के प्रतिबंधित विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो या तो उल्लंघन का गठन करते हैं या अधिकार का आधार बनाते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। व्यापक और अधिक व्यापक अर्थ में, इसका उपयोग भौतिक तथ्यों के पूरे समूह को दर्शाने के लिए किया गया है।

अभिव्यक्ति ''कार्रवाई का कारण'' को आमतौर पर ऐसी स्थिति या तथ्यों की स्थिति के रूप में समझा जाता है जो किसी पक्ष को अदालत या न्यायाधिकरण में कार्रवाई बनाए रखने का अधिकार देता है; प्रवर्त्तनशील तथ्यों का एक समूह जो एक या अधिक आधारों को जन्म देता है; एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अदालत में उपचार प्राप्त करने का अधिकार देती है। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी में ''कार्रवाई का कारण'' ऐसे तथ्यों का पूरा समूह कहा जाता है जो एक प्रवर्तनीय दावे को जन्म देते हैं; इस वाक्यांश में हर वह तथ्य शामिल होता है, जो वादी को निर्णय प्राप्त करने के लिए साबित करना होगा। ''शब्द और वाक्यांश'' (चौथा संस्करण) में वाक्यांश ''कार्रवाई का कारण'' का सामान्य कानूनी भाषा में अर्थ उन तथ्यों का अस्तित्व है, जो किसी पक्ष को उसकी ओर से न्यायिक हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं।

5. इंग्लैंड के हेल्सबरी कानून (चौथे संस्करण) में इसे इस प्रकार कहा गया हैः

"कार्रवाई का कारण" को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अस्तित्व में एक व्यक्ति को न्यायालय से दूसरे व्यक्ति के खिलाफ उपाय प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।यह वाक्यांश प्राचीनकाल से ही माना जाता रहा है कि इसमें हर उस तथ्य को शामिल किया गया है जो वादी को सफल होने का अधिकार देने के लिए साबित होने योग्य है, और हर उस तथ्य को शामिल करता है जिसे पार करने का प्रतिवादी को अधिकार होगा। "कार्रवाई का कारण" भी लिया गया है।इसका मतलब प्रतिवादी की ओर से वह विशेष कार्य है जो वादी को उसकी शिकायत का कारण बताता है, या कार्यवाही के लिए शिकायत का विषय बताता है, न कि केवल कार्यवाही का तकनीकी कारण।"

6. इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्णय संहिता कि पृष्ठभूमि में दिया गया था, जहां तक वर्तमान विवाद का संबंध है, इसकी प्रासंगिकता है।

7. उपरोक्त मामले में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर उच्च न्यायालय के लिए इस मामले पर फिर से विचार करना उचित होगा। तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील का निपटारा किया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेश कुमार जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।